



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श०)

(सं० पटना 620) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 अप्रैल 2017

सं० 22/नि०सि०(पट०)-03-12/14-608—श्री अंबिका प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमण्डल सं०-3, खगौल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 344 दिनांक 04.02.15 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत निम्नलिखित आरोपों यथा:-

(1) सेवापुस्त में जाली हस्ताक्षर के द्वारा सेवा सत्यापन, वेतन वृद्धि एवं अवकाश लेखा अद्यतन किया जाना।
(2) स्वेच्छापूर्वक कार्यालय से अनुपस्थित रहना, अवकाश उपभोग के पश्चात योगदान प्रतिवेदन नहीं देना, उच्चधिकारियों को अपेक्षित सहयोग नहीं करना एवं उनसे उदंडतापूर्वक व्यवहार करना।

(3) उच्चाधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्रों में अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना एवं शिष्टाचार को ध्यान में नहीं रखना, के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपवार निम्न मंतव्य अंकित किया गया:-

(1) सेवापुस्त में दिनांक 01.03.11 से 21.04.12 तक सेवा सत्यापन, दिनांक 01.07.11 की वेतनवृद्धि एवं अवकाश लेखा की प्रविष्टि जाली है, यह प्रमाणित है। परन्तु यह प्रविष्टि आरोपित पदाधिकारी द्वारा ही की गयी है, यह प्रमाणित नहीं है।

विभागीय ज्ञापांक 1848 दिनांक 27.07.05 की शर्तों का उल्लंघन कर कार्यालय द्वारा आरोपित पदाधिकारी को सेवापुस्त उपलब्ध कराया गया एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा भी सेवापुस्त प्राप्त किया गया है। अतएव सेवापुस्त की जाली प्रविष्टि के मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है।

(2) स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, अवकाश उपभोग के पश्चात योगदान नहीं देने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं होता परन्तु उच्चाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग नहीं करने एवं उदंडतापूर्वक व्यवहार करने का आरोप प्रमाणित होता है।

(3) अशिष्ट भाषा का प्रयोग एवं शिष्टाचार के विरुद्ध आचरण करने का आरोप प्रमाणित होता है।

इसी बीच श्री प्रसाद दिनांक 31.08.15 को सेवानिवृत्त हो गए जिसके पश्चात उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की विभागीय आदेश सं० 191 सह पठित ज्ञापांक 2199 दिनांक 28.04.15 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) में सम्पुर्णवर्तित किया गया एवं विभागीय पत्रांक 2378 दिनांक 14.10.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर श्री प्रसाद द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य दिया गया है:-

(1) संचालन पदाधिकारी द्वारा सेवापुस्त में जाली हस्ताक्षर में प्रविष्टि का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसके साथ मार्च, 2011 से जून, 2013 तक का सेवा सत्यापन का पृष्ठ उपलब्ध कराने एवं शंका समाधान का अनुरोध किया गया है ताकि प्रत्युत्तर समर्पित किया जा सके।

(2) आरोप से संबंधित तीन पत्र क्रमशः 1317 दिनांक 11.12.12, 403 दिनांक 24.07.13 एवं 39 दिनांक 23.08.13 का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि प्रथम पत्र उपस्थिति एवं अनुपस्थिति अवधि का है।

इनके पत्रांक 39 दिनांक 23.08.13 द्वारा बकाया वेतनादि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है जिसे साजिश के तहत भुगतान हेतु दबाव बताकर वित्तीय अनियमितता उत्प्रेरित करने का कार्य करने, उच्चाधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं करने तथा उदंडतापूर्वक व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है जो निराधार एवं तथ्य से परे है।

(3) आरोप सं० 3 के संबंध में पत्रांक 22 दिनांक 28.01.14, पत्रांक 38 दिनांक 03.03.14, पत्रांक 41 दिनांक 03.03.14 एवं पत्रांक 46 दिनांक 10.03.14 का पुनः अवलोकन का अनुरोध करते हुए उक्त सारे पत्रों को उपस्थित अवधि के वेतन भुगतान से संबंधित होने जिस पर सरकार का निदेश प्राप्त है, की बात कही गई है। मार्च, 2011 से जून, 2013 की बकाया अवधि का वेतन भुगतान हेतु इनके द्वारा समर्पित अनुपस्थित प्रतिवेदन की जाँच नहीं कराकर भुगतान हेतु सरकार के निदेश का अनुपालन नहीं कर कार्यपालक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमण्डल सं०-3, खगौल, पटना द्वारा तत्कालीन कार्यालय से पत्राचार करने का निदेश उचित नहीं है।

श्री प्रसाद से प्राप्त उक्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षा में निम्न तथ्य पाया गया:—

(1) श्री प्रसाद द्वारा आरोप सं० 1 के संबंध में दिया गया तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वेतनपूर्जा के क्रम में श्री प्रसाद, सहायक अभियंता का सेवापुस्त अविलंब वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग को कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी मुख्य नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर द्वारा भेजा जाना था जिसे गलत नियत से श्री प्रसाद द्वारा स्वयं दिनांक 09.04.13 को बिना अवकाश लेखा के प्राप्त कर लिया गया एवं दिनांक 01.03.11 से 20.04.12 के बीच भिन्न अवधि का सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखा अद्यतन किया गया। इसकी पुष्टि कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी मुख्य नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर के पत्रांक 674 दिनांक 25.11.2013 से होती है। चूँकि उक्त कार्य से केवल श्री प्रसाद ही लाभान्वित हो सकते थे। अतः उनके अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा सेवापुस्त एवं लेखा में प्रविष्टि करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः सेवापुस्त एवं अवकाश लेखा में जाली हस्ताक्षर से प्रविष्टि करने में श्री प्रसाद की संलिप्तता प्रमाणित है।

(2) आरोप सं० 2 के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग नहीं करने एवं उदंडतापूर्वक व्यवहार करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री प्रसाद के प्रत्युत्तर एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में उच्चाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग नहीं करने एवं उदंडतापूर्वक व्यवहार करने का आरोप प्रमाणित है। मार्च 2011 से जून 2013 के बीच भिन्न माहों में स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं अवकाश उपभोग के पश्चात योगदान नहीं देने संबंधी आरोप अप्रमाणित पाया गया है।

(3) आरोप सं० 3 के संबंध में श्री प्रसाद द्वारा कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है जिससे उनके विरुद्ध गठित आरोपों का प्रतिवाद हो सके। संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

समीक्षोपरांत श्री प्रसाद को प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-2215, दिनांक 06.10.2016 द्वारा "20 (बीस) प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक" का दण्ड संसूचित किया गया।

तत्पश्चात श्री प्रसाद द्वारा संसूचित दण्ड के विरुद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 28.12.16 विभाग में समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से उल्लेखित किया गया है कि उनके द्वारा किसी तरह का वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है न ही वे कोई गंभीर कदाचार में लिप्त रहे हैं।

श्री प्रसाद से प्राप्त अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी जिसमें पाया गया कि उनके विरुद्ध आरोप सं०-1 में सेवापुस्त में जाली हस्ताक्षर के द्वारा सेवा सत्यापन करने, वेतनवृद्धि एवं अवकाश लेखा अद्यतन करने का आरोप है। संचालन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में अंकित किया है कि श्री प्रसाद के सेवापुस्त में दिनांक 01.03.2011 में दिनांक 21.4.12 तक का सेवा सत्यापन दिनांक 1.7.11 की वेतनवृद्धि एवं अवकाश लेखा की प्रविष्टि जाली है। विभागीय ज्ञापक-1848, दिनांक 27.7.2005 की शर्तों का उल्लंघन कर कार्यालय द्वारा आरोपित पदाधिकारी को सेवापुस्त उपलब्ध कराया गया एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा सेवापुस्त प्राप्त किया गया। अतएव सेवापुस्त की जाली प्रविष्टि के मामले में इसकी भूमिका संदिग्ध है। सेवापुस्त का जाली सत्यापन करना, वेतनवृद्धि एवं अवकाश लेखा की जाली प्रविष्टि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आती है इसलिए श्री प्रसाद का यह कहना है कि वे गंभीर कदाचार में नहीं रहे हैं को मान्य नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार संचालन पदाधिकारी ने आरोप सं०-2 एवं आरोप सं०-3 को भी प्रमाणित होने का मंतव्य दिया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन में उच्चाधिकारियों को लिखे गए पत्र में अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

समीक्षोपरांत श्री प्रसाद द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य नहीं दिये जाने के कारण अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं०-2215, दिनांक 06.10.16 द्वारा पूर्व में संसूचित निम्न दण्ड को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :-

(1) 20 (बीस) प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक।

उक्त निर्णय श्री अंबिका प्रसाद, तत० सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल सं०-3, खगौल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 620-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>